



न्यायालय राजस्व भण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्र० क० 3371-तीन/2013 विरुद्ध आदेश दिनांक 21.6.2013
-पारित-द्वारा- कलेक्टर, जिला सागर- प्रकरण क्रमांक 29 अ 21/2012-13

- 1- श्रीमती रामवाई पत्नि स्व. लक्ष्मन सौर
 - 2- सुश्री पूनावाई पुत्री लक्ष्मन सौर
 - 3- श्रीमती यशोदा पत्नि तुलाराम सौर
 - 4- अन्नु, विहारी, देवेन्द्र, मुकेश नावालिक
पुत्रगण तुलाराम सौर सरपरस्त माता
श्रीमती यशोदा पत्नि तुलाराम सौर
 - 5- सुश्री रामकुंवर वाई पुत्री तुलाराम सौर
 - 6- देवशराज पुत्र लक्ष्मन सौर
- समस्त निवासी ग्राम महादेवखेड़ी
तहसील बीना जिला सागर म०प्र०
विरुद्ध

--- आवेदकगण

मध्य प्रदेश शासन

---अनावेदक

आवेदकगण के अभिभाषक श्री अजय श्रीवास्तव
म०प्र०शासन के अभिभाषक श्री राजेश त्रिवेदी

आदेश

(आज दिनांक 21.7.2014 को पारित)

यह निगरानी मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत कलेक्टर, जिला सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 29 अ 21/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 21-6-13 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारौंश यह है कि आवेदकगण ने कलेक्टर कार्यालय, सागर में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग की कि उनके नाम ग्राम निवारी तहसील खुरई में आराजी क्रमांक 827 रकबा 1.290 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) है किन्तु वह महादेवखेड़ी मे निवास करते हैं जिसके कारण ग्राम निवारी 30-35 कि.मी. दूर होने से कृषि कार्य नहीं कर पाते हैं।

उनके पुत्र एवं भाई तुलाराम का बीमारी के चलते निधन हो गया है जिनके इलाज एवं तेरहवीं का कर्ज चुकाना है एवं शेष बचे पैसे से रामवाई का इलाज करायेंगे एवं तुलाराम के नावालिक बच्चे की शिक्षा के साथ विवाह पर खर्च करेंगे जिसके कारण भूमि विक्रय की अनुमति दी जावे। आवेदकों के आवेदन की जांच नायब तहसीलदार खुरई द्वारा की जाकर अनुविभागीय अधिकारी खुरई के माध्यम से प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर से कलेक्टर सागर ने आदेश दिनांक 21-6-13 पारित कर विक्रय अनुमति आवेदन निरस्त कर दिया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने गये तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदकगणों के अभिभाषक ने तर्कों में बताया कि वादग्रस्त भूमि आवेदकगण की पट्टे की नहीं है 'पैत्रिक भूमि है जो भूमिस्वामी स्वत्व पर है। भूमि को काविलकास्त बनाने के प्रयास किये गये काफी धन व्यय किया गया किन्तु भूमि उबड़ खाबड़ एवं पथरीली होने से मेहनत बेकार सावित हुई। कलेक्टर महोदय से निवेदन किया गया कि आवेदकगण 30-40 वर्ष से ग्राम महादेवखेड़ा में बस गये हैं वादग्रस्त भूमि वहां से 30-35 किलो मीटर दूर है खेती करने एवं रखवाली करने में असुविधा है। परिवार की सुविधा एवं पैसों की आवश्यकता को देखते हुये बेकार भूमि को बाजिव दामों में विक्रय करने की अनुमति मांगी गई थी जिसे निरस्त करने में कलेक्टर महोदय ने भूल की है उन्होंने विक्रय अनुमति आवेदन स्वीकार किये जाने की मांग की गई। म0प्र0शासन के अभिभाषक ने कलेक्टर के आदेश को यथोचित ठहराते हुये आदिवासियों की भूमि विक्रय से बर्जित होने का तर्क दिया।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद है कि आवेदकगण के नाम ग्राम निवारी तहसील खुरई में आराजी कमांक 827 रकबा 1.290



हैक्टर, जो पैत्रिक होकर पटटे की भूमि नहीं है तथा शासकीय अभिलेख में भूमिस्वामी स्वत्व पर अंकित है। आवेदकगण का विक्रय अनुमति आवेदन तहसील न्यायालय में जांच हेतु भेजा गया है जिस पर नायव तहसीलदार खुरई ने जांच कर प्रतिवेदन दिनांक 30.11.12 प्रस्तुत किया है जिसमें बताया गया है कि आवेदकगण ग्राम में निवास नहीं करते हैं ग्राम से 40 किलो मीटर दूर निवास करते हैं। जांच के दौरान ग्राम पंचायत को सूचना भेजी गई है, ग्राम पंचायत निवारी ने प्रस्ताव/ठहराव दिनांक 27.9.12 से भूमि विक्रय पर आपत्ति नहीं होना बताया है। नायव तहसीलदार ने जांच प्रतिवेदन के कालम नंबर 13 में अंकित किया है भूमि का विक्रय सदभावना पूर्वक है तथा भूमि पटटे की न होकर पैत्रिक है। अनुविभागीय अधिकारी खुरई के समक्ष जांच प्रतिवेदन गया है उन्होंने जांच प्रतिवेदन में खामियाँ बताकर पुनः जांच हेतु प्रकरण नायव तहसीलदार को वापिस किया है और तहसीलदार खुरई ने जो कमियाँ बताई गई थी, पूर्ति कर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी खुरई को भेजा है अनुविभागीय अधिकारी खुरई ने प्रतिवेदन दिनांक 23-5-13 में अंकित किया है कि आवेदकगणों की भूमि पैत्रिक है एवं पटटे की नहीं है प्रकरण कलेक्टर को अग्रेषित कर दिया, जिस पर से कलेक्टर सागर ने आदेश दिनांक 21-6-13 पारित कर विक्रय अनुमति आवेदन खारिज कर दिया।

6/ उपरोक्त पद 5 में की गई विवेचना एवं जांच में आये तथ्यों से यह निर्विवाद है कि वादग्रस्त भूमि आवेदकगणों की पैत्रिक भूमि है एवं पटटे की नहीं है, इसके पूर्व यह भूमि आवेदकगणों के पिता एवं पति के नाम अंकित रही है। पटबारी हलका नंबर 3 द्वारा स्थल निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 10-9-12 में बताया है कि भूमि पटटे की न होकर खरीदी गई भूमि है अर्थात् वादग्रस्त भूमि को आवेदकगण के पिता/पति ने अथवा उसके पूर्वजों ने कय की है तब आवेदकगण के ग्राम निवारी में निवासरत न रहने एवं 40 किलोमीटर दूर के



गाँव महादेवखेड़ा में निवासरत होने से उनके निष्प्रयोज्य की भूमि के विक्रय अनुमति देने में किसी प्रकार की बैधानिक अड़चन है -

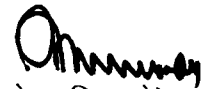
आधुनिक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य तथा एक अन्य 2013 रा. नि. 8 (उच्च न्यायालय) का न्यायिक दृष्टांत इस प्रकार है :-
भू राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.) - धारा 165 (7-ख) में यह उल्लेख नहीं है कि भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगी। इस धारा के उपबंधों से यह स्पष्ट है कि यह भूमिस्वामी द्वारा अर्जित निहित अधिकार छीनती है तथा भूमि के विक्रय के विषय में कलेक्टर से पूर्व अनुमति लेने के सम्बन्ध में नया दायित्व श्रुजित करती है या नया कर्तव्य अधिरोपित करती है, अतएव धारा भूतलक्षी प्रवर्तन होने की उपधारणा नहीं की जा सकती।

जो भूमिस्वामी अधिकार 1978 में दिये गये, संहिता की धारा 165 (7-ख) के अंतर्गत छीने नहीं जा सकता। भूमिस्वामी को विक्रय करने का निहित अधिकार है उनके अधिकार संहिता की धारा 165 (7-ख) के अंतः स्थापन से उन्मुक्त तथा अप्रभावित हैं और संहिता की धारा 158 (3) की स्थिति वही रहेगी, क्योंकि यह 28-10-1992 के संशोधन द्वारा अंतः स्थापित की गई है।

प्रशासकीय सदस्य राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 278-दो-2007 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 16 जुलाई 2010 में यही निष्कर्ष दिये हैं कि 10 वर्ष पश्चात् पट्टाधारी भूमिस्वामी हो जाने के बाद भूमि विक्रय कर सकता है और भूमि विक्रय के पूर्व कलेक्टर की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।

वादग्रस्त भूमि पट्टे की भूमि न होकर आवेदकगण के पूर्वजों द्वारा कय की गई भूमिस्वामी स्वत्व होने से एवं आवेदकगण के परिवार में उपजी परिस्थितियों के कारण विक्रय की अनुमति दिये जाने में किसी प्रकार की बैधानिक अड़चन नजर नहीं आती है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर, जिला सागर द्वारा प्र.क. 29 अ 21/2012-13 में पारित आदेश दि. 21-6-13 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा आवेदकगणों को ग्राम निवारी स्थित भूमि सर्वे कमांक 827 रकबा 1.290 हैक्टर विक्रय पत्र संपादित होने के दिनांक को शासन द्वारा निर्धारित गाईड लायन के मान से विक्रय करने की अनुमति प्रदान की जाती है।



(अशोक शिवहरे)

सदस्य

राजस्व मण्डल, ग्वालियर